बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 177 ● नई दिल्ली ● सोमवार 14 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

ग्रेनो में सांड से बचने के लिए घुमाई स्कूटी, कैंटर की चपेट में आने से महिला की मौत

ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में स्कूटी सवार दंपती को कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही पति को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना रविवार सुबह साढ़े 11 बजे के करीब की है। चौकी इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि सोसायटी की रहने वाली 55 वर्षीय सरिता अपने पति राजनारायण के साथ फल व सब्जी खरीदने के लिए निकली थी। महागुन मार्ट के समीप फल व सब्जी खरीदने के बाद दोनों स्कूटी पर सवार होकर वापस लौटने लगे। अचानक सामने से सांड आ गया।

पीएम मोदी ने राज्यसभा के लिए नामित चारों हस्तियों को दी बधाई, कहा- इनके योगदान से समृद्ध होगा संसद

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए चारों लोगों को शुभकामनाएं दी। इसमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम, केरल भाजपा नेता सी सदानंदन मस्ते और इतिहासकार मीनाक्षी जैन का शामिल है। बता दें कि शनिवार रात को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80(1)(क) के खंड (3) द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा के लिए चार लोगों को मनोनीत किया है। इनमें सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सी. सदानंदन मस्ते, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद् मीनाक्षी जैन का नाम शामिल है। ये नामांकन पूर्व में नामित सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण खाली पड़ी सीटों को मद्देनजर किए गए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को राज्यसभा के लिए नामित किए गए चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनकी ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता से संसद में राष्ट्रीय विमर्श और समृद्ध होगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सम्माननीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामांकित किए गए प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉ. मीणाक्षी जैन जी, पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला जी, समाजसेवी सी. सदानंदन मस्ते जी और वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम जी को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी महानुभाव अपने क्षेत्रों के दिग्गज है और उनके अनुभव से संसद में राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर और बेहतर चर्चा हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उज्ज्वल निकम का विधायी क्षेत्र और संविधान के प्रति समर्पण प्रशंसनीय है। वह न केवल एक सफल वकील रहे है, बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय की प्राप्ति के लिए भी अग्रणी रहे हैं। उनका नामांकन राज्यसभा में उनके उत्कृष्ट कार्य का सम्मान है। वहीं पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को राज्यसभा में नामित होने पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ बताया। पीएम मोदी ने श्रृंगला की सराहना करते हुए कहा कि वह एक श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ और रणनीतिक विचारक है। भारत की विदेश नीति में उनके योगदान ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका नामांकन राज्यसभा में भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण को और समृद्ध करेगा।

अन्याय के सामने न झुकने की मिसाल सदानंदन मस्ते

साथ ही केरल भाजपा नेता और शिक्षक सदानंदन मस्ते को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदानंदन मास्ते का जीवन साहस और अन्याय के सामने न झुकने की मिसाल है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक है।

मीनाक्षी जैन को बताया कुशल शोधकर्ता

वहीं अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने मीनाक्षी जैन के राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी जैन एक कुशल शोधकर्ता और इतिहासकार हैं, जिनका काम शिक्षा, साहित्य और राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। उनका नामांकन राज्यसभा में हमारे अकादमिक दृष्टिकोण को और समृद्ध करेगा।

वो तो सरकार की कठपुतली बन गया है, कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग (ईसी) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि यह संस्था अब मोदी सरकार की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया और दावा किया कि यह प्रक्रिया बहुसंख्यकवादी सरकारों को सत्ता में बनाए रखने का प्रयास है। पूर्व कानून मंत्री सिब्बल ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी ब्लॉक स्तर के अधिकारी के माध्यम से यह तय करना कि कौन नागरिक है और कौन नहीं, संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया गरीब, दलित और आदिवासी वोटरों के नाम हटाकर बहुसंख्यक सरकार के पक्ष में चुनाव परिणाम तय करने का तरीका है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म होती गई है। उनका कहना है कि हर नया चुनाव आयुक्त अपने पूर्ववर्ती से भी अधिक सरकार के अनुकूल काम करता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब से यह सरकार आई है, आयोग की स्वतंत्रता पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम टिप्पणियों पर सवाल किया गया तो सिब्बल ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि वे खुद इस मामले में अधिवक्ता हैं, इसलिए कोर्ट के निर्देशों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग कोर्ट की बातों को गंभीरता से लेगा और विवाद को आगे नहीं बढ़ने देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को एफआईआर में वैध दस्तावेजों के रूप में भी स्वीकार करे। हलांकि आयोग के वकीलों ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे आयोग को बाध्य नहीं कर रहे, लेकिन आयोग को उचित कारणों के साथ फैसला लेना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को वह सब करना चाहिए जो संवैधानिक रूप से उसके अधिकार में है, लेकिन जो अधिकार नहीं है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 10 याचिकाओं पर 28 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने आयोग को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। उसके बाद याचिकाकर्ता भी अपना जवाब देंगे। कोर्ट ने स्क्रूकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए तीन प्रमुख मुद्दों को चिन्हित किया है ह्र आयोग की शक्तियां, प्रक्रिया का तरीका और समय-सीमा। ये तीनों पहलू आने वाली सुनवाई में अहम होंगे।

कूड़े के पहाड़ होंगे साफ, सीएम रेखा गुप्ता और मेयर ने बनाई खास रणनीति

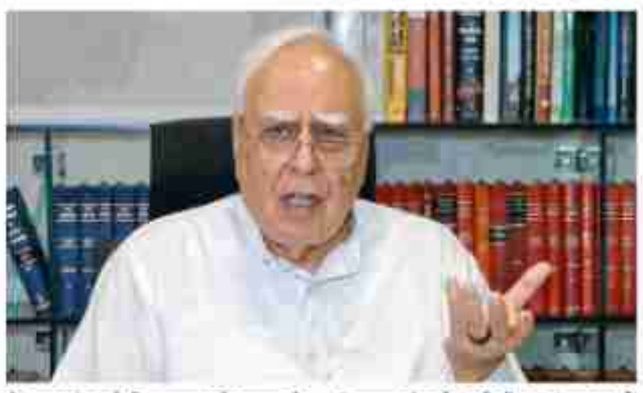

नई दिल्ली। दिल्ली में लंबे समय से बड़ी समस्या बने गाजीपुर, भलस्वा और ओखला के कूड़े के पहाड़ों को हटाने को लेकर अब सरकार ने कमर कस ली है. इसी मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह और निगम अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. इस हाई लेवल मीटिंग में 13 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य फोकस कूड़े की बायोमाइनिंग और लैंडफिल साइटों की सफाई पर रहा. बैठक में तय किया गया कि गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में मौजूद कूड़े के पहाड़ों को वर्ष 2026 की तय समयसीमा से पहले पूरी तरह साफ कर लिया जाएगा. इसके लिए बायोमाइनिंग की क्षमता को जुलाई 2025 से 25,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 30,000 TPD कर दिया गया है. इससे कचरा हटाने की रफ्तार और तेज होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि जब लैंडफिल साइट पूरी तरह साफ हो जाए, तो उस जमीन का एक-तिहाई हिस्सा स्कूल, अस्पताल और खेल परिसर जैसे जनहित कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए, बाकी जमीन पर भविष्य की कूड़ा प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण होगा, जिससे आगे चलकर कचरे की समस्या न बढ़े. महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि नरेला-बवाना में 3,000 TPD क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट अब पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है. वहीं गाजीपुर में भी एक नया वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार के शहरी मंत्रालय से वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी मंजूरी मिल गई है. घोघा डेयरी में 100 TPD क्षमता वाला एक नया CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) प्लांट 15 अगस्त 2025 को शुरू किया जाएगा. इससे गीले कचरे का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा. सरकार डेयरी कचरे के लिए और भी बायोगैस प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है. इस बैठक में उपमहापौर जय भगवान यादव, नेता सदन प्रवेश वाही, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्य शर्मा, उपाध्यक्ष सुंदर सिंह, निगम आयुक्त अश्वनी कुमार, अपर आयुक्त जितेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.

नशे में धुत ऑडी ड्राइवर का कहर : दिल्ली में फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को रौंदा, एक आठ साल की बच्ची भी शामिल

नई दिल्ली।

वसंत विहार इलाके में नौ 8 और 9 जुलाई की देर रात नशे में धुत एक तेज रफ्तार ऑडी कार चालक ने फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद चालक कार समेत भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने कार चालक शेखर (40) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर पुलिस ने घायलों लाधी (40), उनकी बेटी बिमला (8), पति सबामी उर्फ चिरमा (45), राम चंदर (45) और उसकी पत्नी नारायणी (35) को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेडिकल जांच में कार चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है।

पुलिस ने उसके खिलाफ शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाने से हुआ हादसा का मामला दर्ज कर लिया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि घटना 8 और 9 जुलाई की देर रात करीब 1.45 बजे हुई थी। घायल होने वाले दोनों परिवार के सदस्य मूलतः राजस्थान के रहने वाले है और मजदूरी करते हैं। घायल सबामी ने पुलिस को बताया कि घटना के समय सभी फुटपाथ पर सो रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार ने उन्हें कुचल दिया। घटना के बाद चालक कार समेत भाग गया। इसी दौरान एक शख्स उनके पास आया और कागज पर कार नंबर दिया। इसी बीच घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच के दौरान ही पुलिस को पता चला कि एक ऑडी कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस को कार नंबर के जरिए पता चला कि यह वही कार है, जिसने फुटपाथ पर लोगों को कुचला है, पुलिस ने कार चालक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित रामचंदर ने कहा, हम सो रहे थे जब रात के करीब एक बजे कार ने हमें टक्कर मारी... दो लोग घायल हुए। मेरी पत्नी के कान में भी चोट लगी और उसकी पसली टूट गई। पुलिस हमें अस्पताल ले गई। ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

राजधानी के कुछ इलाकों में हुई झमाझम बारिश, सुहावना हुआ मौसम; इस सप्ताह भी खूब बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। फिरोज शाह रोड समेत कुछ इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह भी दिल्ली और आस पास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। 17 जुलाई तक अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में मानसून की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना है। फिरोज शाह रोड पर सुबह के समय बारिश के दृश्यों ने जहां कुछ लोगों के लिए राहत भरी तस्वीरें पेश की, वहीं निचले इलाकों

में जलभराव ने स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि जल निकासी व्यवस्था की कमी के कारण हर बारिश में सड़कें तालाब बन जाती हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए टीमें तैनात करने का दावा किया है। यातायात पुलिस ने लोगों से प्रभावित क्षेत्रों में सावधानी बरतने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। बारिश से तापमान में कमी आई है, लेकिन दिल्लीवासियों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है।

त्रिपुरा की स्नेहा देबनाथ दिल्ली में लापता, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हस्तक्षेप किया

नई दिल्ली। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम की 19 वर्षीय स्नेहा देबनाथ कथित तौर पर दिल्ली में लापता हो गई है. इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने पुलिस को तत्काल और उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए है. अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने इसे लेकर एक पोस्ट किया है. जिसमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सबरूम निवासी स्नेहा देबनाथ, जो कथित तौर पर नई दिल्ली में लापता हो गई है, की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आई है. इसके बाद, पुलिस को तत्काल और उचित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. नई दिल्ली में रहस्यमय परिस्थितियों में देबनाथ के लापता होने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने त्वरित हस्तक्षेप किया और दिल्ली पुलिस तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के नेतृत्व में गहन तलाशी अभियान चलाया गया.दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज की छात्रा स्नेहा आखिरी बार 7 जुलाई को अपने परिवार से संपर्क में थी. उसके परिवार के अनुसार, उसने अपनी मां को बताया था कि वह अपनी एक दोस्त, पितुनिया के साथ सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन जा रही है. उसने आखिरी बार सुबह 5-56 बजे फोन किया था. चिंता तब और बढ़ गई जब सुबह 8-45 बजे तक उसका फोन बंद पाया गया, और बाद में पुष्टि हुई कि पितुनिया उस सुबह स्नेहा से योजना के अनुसार नहीं मिली थी.एक परेशान करने वाली घटना में, परिवार द्वारा पकड़े गए एक कैब ड्राइवर ने पुष्टि की कि उसने स्नेहा को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास छोड़ा था, जो सुरक्षा चिंताओं और खराब सीसीटीवी कवरेज के लिए जाना जाता है. उस इलाके में निगरानी फुटेज की कमी ने स्नेहा की अंतिम गतिविधियों को फिर से बनाने में जांचकर्ताओं को गंभीर रूप से बाधा पहुंचाई है. आपको बता दें कि 9 जुलाई को, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एनडीआरएफ की सहायता से सिग्नेचर ब्रिज क्षेत्र के सात किलोमीटर के दायरे में व्यापक तलाशी अभियान चलाया. हालांकि, तलाशी में कोई ठोस सुराग नहीं मिला.परिवार के सदस्य बेहद चिंतित है, क्योंकि उनका कहना है कि स्नेहा बिना कोई सामान लिए चली गई और पिछले चार महीनों में उसने कोई पैसा नहीं निकाला। उसके बैंक खाते से कोई राशि नहीं निकाली गई है.अधिकारियों ने एक सार्वजनिक अपील जारी की है, जिसमें स्नेहा के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने का आग्रह किया गया है. मामले की गहन जांच जारी है और तलाशी अभियान लगातार तेज होता जा रहा है.

देशभर में मतदाता सूची संशोधन की तैयारी, ईसी ने शुरू किया काम; बिहार में बवाल के बाद उठे थे सुप्रीम सवाल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अगले महीने से पूरे भारत में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी शुरू कर दी है। यह पुनरीक्षण बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण जैसा होगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह कदम उस समय उठाया गया है जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधानिक दायित्व करार दिया और चुनाव आयोग को बिहार में इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी। बता दें कि, चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ कुछ विपक्षी पार्टियों और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पुनरीक्षण के खिलाफ चुनौती दी थी, उनका कहना था कि इससे योग्य नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिल सकता है। अब कुछ राज्य चुनाव अधिकारियों ने उन राज्यों में आखिरी बार किए गए विशेष पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित मतदाता सूची को सार्वजनिक कर दिया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जब राष्ट्रीय राजधानी में आखिरी बार पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में 2006 में आखिरी पुनरीक्षण हुआ था, और अब उस वर्ष की सूची राज्य की वेबसाइट पर है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 28 जुलाई को बिहार मामले की सुनवाई के बाद, वह देशव्यापी पुनरीक्षण पर अंतिम निर्णय लेगा। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी अवैध प्रवासियों को उनके जन्मस्थान की जांच करके हटाया जाएगा। वहीं राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने है। जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अगले साल में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग का देशव्यापी मतदाता सूची पुनरीक्षण करने का फैसला बांग्लादेश और म्यांमार समेत कई राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।

दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश! कांवड़ियों के मार्ग पर फैलाए कांच के टुकड़े

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर एक साजिश के अंतर्गत माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। शाहदरा के इलाके में कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग पर एक किलोमीटर तक कांच के टुकड़े तोड़े गए हैं। इसकी जानकारी आते ही माहौल गर्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने भरोसा जताया है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के कांवड़ियों ने 11-12 जुलाई को हरिद्वार के हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थानों से गंगा का जल उठाया है। वे आज अलग-अलग समय पर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के कई शिवालयों में 13 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को गंगा जल अर्पित किया जाएगा। लेकिन रविवार सुबह ही सूचना मिली कि कांवड़ियों के आने वाले मार्ग पर कांच के टुकड़े फेंके गए है। इससे लोगों में नाराजगी फैल गई। लेकिन दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी होते ही इस पूरे मार्ग की साफ-सफाई की गई। हर जगह पर सफाई कर्मचारियों को लगाकर कांच के टुकड़े हटाए गए। पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है जिससे इस घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचा जा सके। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने यह मामला सामने आते ही इस पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों को दिल्ली में हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी और उनके मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के लिए विशेष सुरक्षित मार्ग बनाया है जिस पर कोई अवरोध नहीं आने दिया जाएगा। कांवड़ियों के आराम करने हेतु दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड संख्या में कांवड़ शिविर लगाए गए है। इस बार दिल्ली में रिकॉर्ड 374 कांवड़ शिविर बनाए गए हैं। पिछले वर्ष यह संख्या सौ से कुछ ही ज्यादा थी। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने हर कांवड़ शिविर को मुफ्त बिजली के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है।

द्वारका के रेडिसन ब्लू होटल में भीषण आग, सौना रूम से उठीं लपटें

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित रेडिसन ब्लू होटल में रविवार तड़के आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार आग होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित सौना रूम में लगी थी. हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात रही. दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. दमकल विभाग के अनुसार, घटना के तुरंत बाद कई दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया. आग सौना रूम तक ही सीमित रही, जिससे होटल के अन्य हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. दमकल अधिकारियों ने समय पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया. सहायक मंडल अधिकारी रवि नाथ ने जानकारी देते हुए बताया, हमें रात 12:17 बजे कॉल मिली कि द्वारका के रेडिसन ब्लू होटल में आग लग गई है. जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, तब दूसरी मंजिल पर स्थित सौना रूम में आग धधक रही थी. हमने तुरंत बचाव और आग बुझाने का कार्य शुरू किया. जल्द ही आग को काबू में कर लिया गया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. शुरुआती जांच के मुताबिक, आग सौना रूम में किसी तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है. हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. होटल प्रबंधन ने भी इस घटना पर तुरंत एक्शन लिया और सभी मेहमानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. अधिकारियों द्वारा तकनीकी जांच के बाद ही इसकी पुष्टि की जाएगी. फिलहाल, होटल को अस्थायी रूप से खाली करवा दिया गया है और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही दोबारा संचालन शुरू होने की उम्मीद है. बता दें इससे पहले दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शनिवार दोपहर आग लगी थी. वहां एक दुकान की पहली मंजिल पर भीषण आग गई थी. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया था.

क्या अब राजनाथ होंगे भाजपा अध्यक्ष ?

त्रिदीब रमण

लगता है आने वाले कुछ दिन इन कयासों पर विराम लगाने वाले हैं कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? संघ के आंगन से छन कर आई नेपथ्य की आहटों को अगर ठीक से पहचाना जाए तो नए अध्यक्ष की दावेदारी में राजनाथ सिंह सबको बड़े सिरमौर बन कर उभरे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि नई दिल्ली के केशव कुंज में 4 से 6 जुलाई तक संघ के प्रांत प्रचारकों की तीन दिवसीय बैठक आहूत थी, जिसमें मोहन भागवत समेत संघ के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति दर्ज हुई। संघ और इसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े कोई 233 अहम स्वयंसेवकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों की मानें तो संघ के कोर ग्रुप की बैठक में भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर गंभीर मंत्रणा हुई। इस कड़ी में चार-पांच भाजपा नेताओं के नाम गिनाए गए थे। पहला नाम नितिन गडकरी का था, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान के नाम उभर कर सामने आए हैं। आखिरकार संघ ने राजनाथ सिंह का नाम आगे कर दिया है। मृदुभाषी राजनाथ सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं और वे सरकार व संगठन की ताकत में संतुलन साधने की बाजीगरी में भी उतने ही सिद्धहस्त साबित होंगे। हालिया 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद राजनाथ सिंह की लोकप्रियता में भी किंचित इजाफा हुआ है, सो बिहार-बंगाल के चुनाव में पार्टी को इनके नाम का फायदा भी मिल सकता है। आने वाले 21 जुलाई से संसद के मानूसन सत्र का आगाज़ होने वाला है। संघ से जुड़े सूत्र स्पष्ट करते हैं कि मौजूदा दौर में संघ में भी दो अलग धाराओं का अभ्युदय देखा जा सकता है। इनमें से एक धारा का प्रचलित नाम 'ट्राड' (ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक) है जो संघ की मूल भावनाओं को ही मजबूती से अभिव्यक्त करता है। कहते हैं इस धारा का प्रतिनिधित्व स्वयं सर संघचालक मोहन भागवत करते हैं। इस धारा के लोगों की मान्यता है कि संघ की स्थापना जिन मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर हुई है उससे ज्यादा डिगना नहीं चाहिए। सो, इस धारा के लोग हिंदुत्व, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को आगे लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, इस धारा के देदीप्यमान नक्षत्र के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है। संघ का इन्हें पुरजोर समर्थन उन्हें हासिल है। संघ के नंबर दो माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले किंचित उदारवादी विचारधारा को आगे ले जाने के पक्षधर हैं। संघ का यही गुट है जो मानता है कि वर्तमान दौर में इतने कट्टर अप्रोच के साथ बात नहीं बनने वाली है, अपने इस सौवें वर्ष में संघ को अपना 'सर्वधर्म समभाव' वाला एक उदारवादी चेहरा सामने रखना होगा। केवल हिंदुत्व से बात नहीं बनेगी, जरूरत पड़ने पर मुस्लिम व दलितों को भी संघ की विचारधारा से जोड़ना होगा। यह खेमा दलित व अति पिछड़ों को संघ व भाजपा की विचारधारा के करीब लाने की वकालत करता रहा है। मौजूदा भाजपा नेतृत्व को भी इसी धारा का पैरोकार माना जा सकता है। राजनाथ सिंह के नए भाजपाध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी में भाजपा की भी उतनी ही दिलचस्पी है। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी जदयू के परंपरागत वोट बैंक में शुमार होने वाली अति पिछड़ी जातियों का इस चुनाव में कुछ अलग रुख हो सकता है। अति पिछड़ी जातियों की तादाद बिहार में सबसे ज्यादा है कोई 37 फीसदी के आसपास। बिहार के पिछले 4-5 बार के विधानसभा चुनाव इस बात के गवाह हैं कि कैसे नीतीश ने इन जातियों को अगड़ों व यादवों के डंड का भय दिखा अपने तीर-कमान से नाथ लिया था। इस बार अगड़े वोट एकमुश्त भाजपा की झोली में जा सकते हैं, इसकी प्रतिक्रिया में अति पिछड़े वोटर जदयू व भाजपा से छिटक सकते हैं। नीतीश के खराब स्वास्थ्य व उनकी अस्थिर भाव- भंगिमाओं ने भी उनके कोर वोटरों में एक संशय का भाव पैदा किया है। अति पिछड़े वोटरों की काफी पहले से यह शिकायत रही है कि 'उनके नाम की सारी मलाई तो ईबीसी की तीन जातियां यानी कलवार, सूरी व तेली खा जाते हैं, इन्हीं तीन जातियों को ज्यादातर प्रतिनिधित्व एमपी, एमएलए का चुनाव लड़ने व जीतने में भी मिल जाता है। बड़े सरकारी पदों पर भी ईबीसी में ज्यादातर इन्हीं तीन जातियों का बोलबाला है।' सो, बाकी की ईबीसी जातियां चाहती हैं कि 'कलवार, तेली व सूरी जाति को एक्सट्रा यानी ओबीसी जाति में डाल दिया जाए।' ईबीसी के अंतर्गत आने वाली 100 जातियां तो ऐसी हैं जिनकी संख्या एक लाख से भी कम है, सो आगामी विधानसभा चुनाव में ईबीसी जातियों की मुख्य चिंता यही है कि उन्हें अलग-अलग सदनों में उचित प्रतिनिधित्व कैसे मिले। राजस्थान की भगवा महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की एक बार फिर से भाजपा में पूछ बढ़ गई है। विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि एक बड़े नेता ने महारानी को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। कहते हैं यह मुलाकात लंबी चली, राजस्थान को लेकर बड़े नेता ने वसुंधरा से एक के बाद एक कई सवाल पूछे और यह जानना चाहा कि 'इतने कम समय में ही प्रदेश की भजन लाल सरकार से जनता का मोहभंग होना क्यों शुरू हो गया है?' भाजपा नेता ने वसुंधरा को केंद्र में मंत्री बनने का प्रस्ताव भी दिया और कहा-अगली बार जब भी वे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उसमें वह वसुंधरा को एक अहम मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपेंगे। कहते हैं वसुंधरा ने बेहद विनम्रतापूर्वक तरीके से कहा- मैं दिल्ली में रह कर आपके लिए राजस्थान नहीं बचा पाऊंगी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंत्री हूं या नहीं, आप मुझे एक बार फिर से राजस्थान की कमान सौंपिए, मैं वहां कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ पर लगाम लगा पाऊंगी। कहते हैं वसुंधरा ने यह भी कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में महज 66 सीटें ही जीत पाई थी,

हमने जीती 118, पर आज स्थितियां पलट गई हैं, आज चुनाव हो गए तो कांग्रेस 120 सीटें भी जीत सकती है। सो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में भाजपा नेतृत्व राजस्थान को लेकर किसी बड़े निर्णय पर पहुंच जाए। संघ की तीन दिवसीय दिल्ली बैठक में भाजपा शासित तीन प्रदेशों के सीएम के कामकाज को लेकर गंभीर नाखुशी जताई गई है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि भाजपा को जिताऊ बनाने के लिए संघ के समर्पित कार्यकर्ता रात-दिन एक कर देते हैं, मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लामबंद करने के लिए 'डोर-टू-डोर कैंपेन' चलाते हैं, पर जब पार्टी इन मुख्यमंत्रियों के हाथों में राज्य का बागडोर थमाती है तो कैसे ये अपना घर भरने में लग जाते हैं। कहते हैं संघ ने अपनी भावनाओं से भाजपा शीर्ष को अवगत करा दिया है। इसी बैठक में एक और बात पर चर्चा हुई कि अब भाजपा को 'सेलिब्रेटी स्टार' को पार्टी टिकट देने का मोह त्यागना होगा। मिसाल के तौर पर हेमा मालिनी का नाम लिया गया कि कैसे उनके बयान पर मथुरा-वृंदावन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा एक और चर्चित बॉलीवुड अदाकारा का भी नाम लिया गया। भोजपुरी फिल्म जगत व खेल जगत से एमपी-एमएलए बने लोग कैसे पार्टी के विचारों का संवर्धन कर रहे हैं? सवाल इस पर भी उठा। संघ की मान्यता थी कि ऐसे लोगों को पार्टी का टिकट दिया जाना चाहिए जो भाजपा व संघ के विचारों से मिलते हुए लोग हों या इसे आगे ले जाने का माद्दा रखते हों। संघ ने खुद भी एक संज्ञान लिया है और बैठक में कहा गया कि अब संघ के विचारों को भी आगे ले जाने के लिए हमें अपना चेहरा-मोहरा बदलना होगा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ना होगा। बिहार में चुनाव आयोग की पहल से चर्चा में आए 'वोटर लिस्ट रिवीजन' का मामला सत्ताधारी दल के लिए उल्टा दांव साबित हो सकता है। राज्य की विपक्षी पार्टियां बहुत हद तक राज्य की गरीब व अल्पसंख्यक मतदाताओं को समझाने में कामयाब दिख रही है कि मौजूदा सरकार उनसे उनका वोट का अधिकार छिनना चाहती है।

संविधान और 'एक' चुनाव

एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में लाये गये संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की ही संयुक्त समिति विचार कर रही है। समिति का कार्य है कि वह विधेयक के विभिन्न कानूनी व व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करके अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट संसद को भेजे। फिलहाल भारत में जो व्यवस्था है उसके तहत लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग समय पर होते रहते हैं और भारत का चुनाव आयोग इन्हें सम्पन्न कराता है। इसे देखते हुए शायद ही कोई ऐसा वर्ष खाली जाता है जिसमें किसी न किसी विधानसभा के चुनाव न होते हों। इसके अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव भी अलग-अलग राज्यों में होते रहते हैं जिनमें ग्राम पंचायतें भी आती हैं। मगर वर्तमान की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पिछले दो दशकों से पैरवी करती आ रही है कि पूरे देश में एक बार ही लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव कराये जाने चाहिए। भाजपा पिछले दो दशक से इस मामले को अपने चुनाव घोषणा पत्र का भी अंग बनाये हुए है। मगर भाजपा से विरोध रखने वाले लगभग सभी दल इसकी मुखालफत करने में भी पीछे नहीं हैं। इसी मुखालफत को ध्यान में रखते हुए इस बाबत लाये गये संविधान संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। इस समिति की अभी तक कई बैठकें हो चुकी हैं जिनमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी सलाह भी ली गई। समिति की पिछली बैठक गत शुक्रवार को हुई, जिसमें भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों सर्वश्री डी.वाई. चन्द्रचूड़ व जे.एस. खेहर ने भाग लिया और अपने विचारों से अवगत कराया। समझा जाता है कि श्री चन्द्रचूड़ ने समिति को बताया कि एक देश-एक चुनाव का विचार संविधान विरोधी नहीं है और न ही संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। वैसे संसद की किसी भी स्थायी या प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति की बैठक की कार्यवाही विशेषाधिकार सम्पन्न होती है और इसमें हुई बातचीत या विचार-विमर्श को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मगर इस समिति के अध्यक्ष श्री पी.पी. चौधरी ने एक ट्वीट जारी कर इसकी बैठक की वे दो तस्वीरें सार्वजनिक कीं जिनमें न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ व जे.एस. खेहर अपनी बात रख रहे हैं। अतः समिति की बैठक की कार्यवाही के अंश भी छन-छन कर बाहर आये लगते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का मत जानें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधेयक का वर्तमान प्रारूप संविधान की कसौटी पर संभवतः खरा न उतरे क्योंकि इसमें भारत के चुनाव आयोग को असीमित अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों के चलते चुनाव आयोग यदि आपे से बाहर हो जाये तो उससे भारत के संसदीय लोकतन्त्र पर चोट पहुंच सकती है।

विधेयक का यह पक्ष वास्तव में बहुत ही गंभीर है। हमारे संविधान में किसी भी संवैधानिक संस्था को स्वेच्छाचार की छूट नहीं दी गई है और सभी को किसी न किसी रूप में जवाबदेह बनाया गया है। यहां तक कि संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति को भी यह छूट नहीं है और उन पर भी संसद में महाअभियोग लगाने का दरवाजा खुला रखा गया है। इसलिए यदि न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ व खेहर विधेयक के बारे में अपनी राय संवैधानिक नुक्तों के साथ दे रहे हैं तो उसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। पूरे मामले को यदि हम स्वतन्त्रता के बाद के संसदीय चुनावी इतिहास के सन्दर्भ में परखें तो साफ होता है कि एक देश-एक चुनाव का विचार किसी भी कोण से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। तथ्य यह है कि स्वतन्त्र भारत में 1967 तक लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हर पांच साल बाद ही हुआ करते थे और भारत के मतदाता दोनों सदनों के लिए अपने वोट का प्रयोग किया करते थे। भारत के मतदाताओं की परिपक्वता का इस हकीकत से ही पता चलता है कि 1967 में जहां उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया था वहीं देश के राज्यों की नौ विधानसभाओं में इसे गद्दी से उतार दिया था। उस समय नौ राज्यों में विपक्षी दलों ने आपस में मिलकर सरकारें बनाई थीं और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। पूरे देश में एक बार में ही चुनाव कराये जाने के खिलाफ यह तर्क दिया जाता है कि इससे मतदाता भ्रम में पड़ जायेगा। यह तर्क पूरी तरह आधारहीन है। इसलिए वर्तमान समय में हम यदि एक साथ ही विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव कराने के संवैधानिक रास्ते खोज रहे हैं तो इसे लोकतन्त्र विरोधी किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता। वैसे इसके खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध क्षेत्रीय दलों की तरफ से ही आ रहा है। यहां भी हमें 1967 में हुए चुनाव परिणामों का संज्ञान लेना होगा। इन चुनावों के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की राजनीति की शुरुआत हुई। कालान्तर में ये दल कुछ राज्यों में काफी मजबूत होते चले गये। मगर इसके बाद से देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहने का सिलसिला भी चल पड़ा जिससे चुनाव सम्पन्न कराने का खर्चा भी बढ़ता चला गया। वैसे बार-बार चुनाव होना लोकतन्त्र में कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में आम मतदाता ही इसका मालिक होता है लेकिन बार-बार चुनाव होने से देश के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार बंध जाती है और सरकारी खर्च अलग से बढ़ जाता है। इस मुद्दे का यह पक्ष ऐसा है जिस पर आम मतदाता को भी गौर करना चाहिए। मगर असली मुद्दा यही है जिस तरफ पूर्व मुख्य न्यायाधीश ध्यान दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि एक देश-एक चुनाव के जुनून में चुनाव आयोग को स्वच्छन्द होने की आजादी नहीं दे सकते हैं। अतः समिति को भी इस मुद्दे पर गहरा चिन्तन-मनन करना होगा।

पिछले जन्म के पापों को धोने का सुअवसर!

सरकार जी देश में लौट आये हैं। यह खबर है। सरकार जी का विदेश जाना इतनी बड़ी खबर नहीं बनती है जितनी बड़ी खबर लौट आना बनती है। तो बड़ी खबर यह है कि सरकार जी लौट आये हैं। वैसे सरकार जी का विदेश जाना भी इस बार बड़ी खबर बना क्योंकि सरकार जी कई छोटे छोटे देशों से बड़ा बड़ा सम्मान इशु करा लाये। किसी देश ने अपना सबसे ऊपर वाला सम्मान दे दिया तो किसी देश ने ऊपर वाले से नीचे वाला। सरकार जी तो अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर किसी भी देश जा सकते हैं लेकिन उनकी कोशिशों से हमें कहीं भी जाना मुश्किल हो गया है। उनके एफर्ट से हम सब भारतीयों का पासपोर्ट दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। यह उनका ही प्रताप है कि हमारा पासपोर्ट जो पहले, 2014 में 76वें स्थान पर होता था, अब उन्नति कर 148वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार जी ने इतनी उन्नति से अठारह अठारह घंटे काम करके हासिल की है। अगर सरकार जी पूरे चौबीस घंटे काम करते तो अवश्य ही 199 देशों की रैंकिंग में सर्वोच्च 199वां स्थान प्राप्त करते। कोई बात नहीं, अभी तीन-चार साल बाकी हैं, वह स्थान भी प्राप्त कर लिया जायेगा। वैसे अब विदेश में बसना आसान हो गया है। नहीं, नहीं, अमरीका में, यूरोप के देशों में तो बसना मुश्किल ही होता जा रहा है पर दुबई में बसना आसान हो गया है। मुझे यह खबर मिली और यह खबर मुझे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को दुबई में बसने की यह अच्छी खबर मिली है। यह खबर इतनी व्यापक थी कि बड़े बड़े चैनलों ने भी इस पर कार्यक्रम कर डाले। खबर थी कि मात्र तेईस लाख रुपये खर्च कर आप दुबई में बस सकते हैं। पहले यह मुद्रा साढ़े चार करोड़ रुपये से अधिक होती थी। आपको साढ़े चार करोड़ रुपये या उससे अधिक का मकान खरीदना होता था या उतने ही पैसे दुबई में किसी व्यवसाय में लगाने होते थे। इसलिए अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीयों के लिए और कहीं नहीं तो दुबई में महंगाई जरूर कम हुई है और छप्पर फाड़ कर कम हुई है। कोई चीज जो पहले साढ़े चार करोड़ में मिल रही हो, अब तेईस लाख में मिलने लगे तो कितने प्रतिशत कम हुई। जरा हिसाब तो लगाना। मुझसे तो खुशी के मारे हिसाब ही नहीं लग रहा है। भारत में जीवन यापन भले ही महंगा हो गया हो, पर विदेश में बसना कितना सस्ता हो गया है। सब सरकार जी की ही कृपा है। पहले विदेश में बसना मुश्किल भी था और महंगा भी। सरकार जी की सरकार बनने से पहले तो यह बहुत ही मुश्किल था। या तो वहां इतना पढ़ो कि कोई विदेशी कम्पनी आपको हायर कर ले या फिर विदेश में पढ़ाई पर इतना खर्च करो कि वहीं की कोई कम्पनी वहीं का वहीं तुम्हें हायर कर ले। दोनों के लिए ही दिमाग और पैसा, दोनों ही बहुत लगाना पड़ता था। तब इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते थे। पर अब सरकार जी ने विदेश में बसने की एक और विधि इजाद की है- मनी ड्रेन की। मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान काम है। बस बैंक से हजारों करोड़ का कर्ज लो और विदेश भाग जाओ। कहीं कोई रुकावट नहीं।

सम्पादकीय...

नोटबंदी से लेकर अब बिहार से शुरू वोटबंदी तक

ये क्या अपने मोदी साहब के साथ सरासर चीटिंग नहीं है? माने चीटिंग हो नहीं गयी है। मोदी साहब के साथ चीटिंग इतनी ही आसान है क्या? मोदी साहब जब तक खुद न चाहें, उनके साथ चीटिंग कर जाए, इतनी किस में हिम्मत है। फिर भी चीटिंग की कोशिश तो है। बताइए, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी की खास निशानी है या नहीं? पीएम की कुर्सी पर आने के बाद ग्यारह साल में मोदी जी ने ज्यादा न सही, कम से कम दो-ढाई दर्जन तो मास्टर स्ट्रोक मारे ही होंगे। नोटबंदी से लेकर अब बिहार से शुरू वोटबंदी तक, मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक बिखरे पड़े हैं, गिन तो लें। सच पूछिए तो ग्यारह साल में मोदी जी और मास्टर स्ट्रोक, एक-दूसरे का पर्याय ही हो गए हैं। मोदी जी को पुकारो को मास्टर स्ट्रोक सुनाई देता है। बल्कि अब तो ये आलम है कि मोदी जी जो भी करते हैं, मास्टर स्ट्रोक निकलता है। ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा, मास्टर स्ट्रोक। डियर फ्रैंड ट्रम्प के नोबेल शांति पुरस्कार की खातिर, ऑपरेशन सिंदूर साढ़े तीन दिन में ही झटके से रोक दिया, वह भी मास्टर स्ट्रोक। यहां तक कि पिछले ही दिनों पांच देशों की आठ दिन की यात्रा पर, चार-चार मैडल बटोर लाए, वह भी मास्टर स्ट्रोक। पर अब उसी मास्टर स्ट्रोक को मोदी जी से चुराने की कोशिश हुई है। सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक अपने नाम पेटेंट नहीं कराया था, क्या कोई भी ऐरा-गैरा इस पर अपना अधिकार जमा सकता है। भागवत जी ने क्या सोचा था कि मोदी जी ने पेटेंट नहीं कराया है तो कोई भी मास्टर स्ट्रोक लगाकर निकल जाएगा? कोई भी पचहत्तर साल में रिटायरमेंट की याद दिलाकर, इशारों में मोदी जी से इस्तीफा मांग लेगा और मोदी जी मार्गदर्शक मंडल ज्वाइन करने निकल पड़ेंगे? माना कि भागवत जी भी कोई ऐरे-गैरे नहीं हैं। गैर तो हर्गिज ही नहीं हैं। मोदी जी जिसे अपना मात-पिता संगठन कहते हैं, उसके भी पिता हैं। परम आदरणीय हैं। और सिर्फ चार दिन ज्यादा सही, पर उम्र में भी बड़े हैं, इसलिए भी आदरणीय हैं। पर आदर के चक्कर में मोदी जी, भागवत जी को अपना मास्टर स्ट्रोक थोड़े ही उड़ा लेने देंगे? एक-तरफ मात-पिता संगठन है और दूसरी तरफ, एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों की अंतिम सांस तक सेवा का संकल्प। पलड़ा तो अंतिम सांस तक सेवा का ही भारी रहेगा। वैसे भी भागवत जी उनके मात-पिता संगठन के पिता हैं जरूर, लेकिन वर्तमान ही। मात-पिता संगठन तो स्थायी है, पर उसके पिता आते-जाते रहते हैं। बहुत जल्दी-जल्दी नहीं, किसी के कहने पर नहीं, पब्लिक की डिमांड पर तो हर्गिज नहीं, फिर भी आते-जाते रहते हैं। बायोलॉजीकल जो ठहरे। हमें डर है कि मास्टर स्ट्रोक लगाने के चक्कर में भागवत जी ने अपने जाने का ही टैम न्यौत लिया है? इसी 11 सितंबर को उन्हें भी पचहत्तर साल का शॉल ओढ़ना है। मोदी जी को पचहत्तर साल वाले शॉल में लपेटने के चक्कर में, ऐसा न हो कि भागवत जी खुद ही शॉल में उलझ कर रह जाएं और मोदी को शॉल ओढ़ा ही नहीं पाएं। मोदी जी की नकल कर के मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश हमें तो उल्टी ही पड़ती नजर आती है। आखिर, भागवत जी यह कैसे भूल गए कि मोदी जी साधारण मनुष्य नहीं हैं, जो पैदा होता है, पचहत्तर साल तक चल पाया तो बुजुर्ग होता है, रिटायर होता है और एक दिन देह त्याग देता है। मोदी जी ठहरे नॉन बायोलॉजीकल। उन्हें तो परमात्मा ने इस धरती पर अपने विशेष प्रयोजन से भेजा है। नॉन बायोलॉजीकल के लिए नो बुढ़ापा, नो रिटायरमेंट। और जब बायोलॉजीकल देह ही नहीं तो उसका त्याग कैसा? पचहत्तर साल पर रिटायरमेंट का नियम, भागवतों के लिए हो सकता है, मोदी जी को तो काम पूरा हो जाने के ईश्वरीय संदेश का इंतजार करना होगा। वैसे भागवत जी को भी पचहत्तर साल के करीब फूंककर मास्टर स्ट्रोक लगाकर देखने की ये सूझी भी तो क्या सूझी? मास्टर स्ट्रोक लगाना हर किसी के बस की बात थोड़े ही है। सच पूछिए तो मास्टर स्ट्रोक लगाना किसी अकेले के बस की बात भी नहीं है। क्रिकेट-व्रिकेट की नहीं कहते, पर बाकी हर चीज में मास्टर स्ट्रोक टीम वर्क होता है। और टीमों में टीम, अमृत काल के मीडिया की टीम। मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो यही है कि मीडिया वाली टीम पूरी तरह से उनके पाले में। इसीलिए, जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो रहा है और गेंद कहीं भी जाए, मोदी जी के हरेक शॉट पर मास्टर स्ट्रोक का एनाउंसमेंट हो रहा है। और क्यों न हो, मीडिया के सारे खिलाड़ी मोदी जी के पाले में हैं, क्योंकि सारे मालिक मोदी जी के पाले में हैं। भागवत जी को मास्टर स्ट्रोक लगाने का इतना ही शौक था, तो मोदी जी को बता देते, वह मीडिया की अपनी टीम के सहारे उनके भी दो चार शॉटों पर मास्टर स्ट्रोक का एनाउंसमेंट करा देते। पर मोदी जी के रिटायरमेंट की उछलती हुई गेंद पर मास्टर स्ट्रोक लगाने के लालच में उन्हें नहीं पड़ना चाहिए था। अब तो मोदी जी ही कोई मास्टर स्ट्रोक लगाकर बचाएं तो बचाएं वर्ना भागवत जी जरूर पचहत्तर साल वाले शॉल में लपेटे जाएंगे और मोदी जी दर्शक दीर्घा से तालियां बजाएंगे। रही बात मोदी जी की तो मोदी जी तो फकीर आदमी हैं। झोला उठाकर पब्लिक की सभाओं में निकल जाएंगे, अपने मन की बात सुनाने। विरोधी अब कहते हैं कि मोदी बूढ़ा क्यों नहीं होता? पचहत्तर की उम्र में भी मोदी जवानों से भी ज्यादा जवान है। एक दम सीधा तन कर चलता है, हवाई जहाज की सीढ़ियों से भी बिना रेलिंग का सहारा लिए उतरता है। अठारह-अठारह घंटे पब्लिसिटी का काम करता है। मैं कहता हूं कि यह मेरे एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है, जो मोदी को सदा जवान रखता है। जब तक मेरे देशवासियों का आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है, बुढ़ापा मोदी के आस-पास फटक भी नहीं सकता है। फिर मोदी क्यों रिटायर्ड हो? मोदी के लिए उम्र बस एक संख्या है, आंकड़ा है। मोदी ऐसे खाली-पीली आंकड़ों से डरने वाला नहीं है। वैसे भी ये पचहत्तर साल, रिटायरमेंट, ये सब पश्चिम की बातें हैं। मोदी क्यों करे पश्चिम की नकल? मोदी क्यों ढोए विदेशी गुलामी की निशानियां? हमारी महान परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास कुछ और है। राम, कृष्ण, दोनों राजा थे या नहीं? कोई रिटायर्ड हुआ था क्या? पश्चिम की नकल पर मोदी क्यों रिटायर्ड हो? पर भागवत, तुम भी...!

सरकार का ऑपरेशन कालनेमि- ढोंगी नकली पाखंडी साधु संतों में भारी हड़कंप-सभी राज्यों ने इसका संज्ञान लेना समय की मांग

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियां में संभवतःभारत ही एक ऐसा देश है जिसकी देवभूमि पर,पग-पग पर आध्यात्मिक स्थल है,लोगों में भरपूर धार्मिक आध्यात्मिक आस्था श्रद्धा है, जो एक अच्छी बात है, अभी चल रही अमरनाथ यात्रा व कावड़ यात्रा में हम सभी यह देख रहे हैं ऐसे अनेकों अवसर प्रतिदिन अनेक राज्यों में आते रहते हैं जहां भक्तों की भीड़भाड़ लगी रहती है व सबसे अच्छी बात यह है कि आध्यात्मिक स्थल, ट्रस्ट, अनेकों सेवा समितियां व संस्थाओं द्वारा भक्तों की सेवा व ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी तरह शासन प्रशासन भी भक्तों की सुरक्षा व व्यवस्था में पूर्ण सहयोग करता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि सुरक्षा, सेवा, देखभाल कितनी भी चाक चौबंद क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लीकेजेस होते रहते हैं जिनमें भक्तों को बहुत परेशानी, ठगी, धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है, जो उनसे इस आध्यात्मिक परिसर या बाहर में हो सकता है, उसी का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमि चलाया है, जो मेरे विचार से बहुत ही शानदार पहल है,मैं इसआर्टिकल के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन,अनुरोध करना चाहूंगा कि, कालनेमि, इसका संज्ञान लेकर यह ऑपरेशन तुरंत लागू करें ताकि पूरे भारत में लागू हो जाए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत से देशी विदेशी अपराधिक छवि वाले भी घुसे हुए हैं, जिनकी दुकानदारी जोरों से चल रही है व भक्त ठगी धोखाधड़ी पाखंड का शिकार हो रहे हैं जिनका सटीक उदाहरण है कि,उत्तराखंड सरकार ने यह अभियान चलाकर तेजी से धरपकड़ कर एक ही दिन में 25 से अधिक ऐसे पाखंडी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक पड़ोसी मुल्क का नागरिक भी शामिल है, इस अभियान को कढ़ाई को देखकर अब नकली बाबाओं में भारी हड़कंप मच गया है, व धरपकड़ के डर से भी अपने स्थान छोड़कर अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं इसीलिए सभी राज्यों ने इसका संज्ञान लेकर इसी तरह का अभियान चलाने की जरूरत है,चूंकि आध्यात्मिक आस्था की प्रतीक भारतीय देवभूमि पर आस्था पूजा श्रद्धा के नाम पर ठगी व नकली बाबाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, सरकार का ऑपरेशन कालनेमि-ढोंगी नकली पाखंडी साधु संतों में

> **मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की धार्मिक, जातीय या पंथीय पहचान की परवाह किए बिना राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और सख्त कदम उठाएगी, जनता से यह अपील गई गई है कि अगर उन्हें किसी भी फर्जी बाबा या ढोंगी के बारे में जानकारी हो, तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें, ताकि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा सकें,सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए,उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की धार्मिक, जातीय या पंथीय पहचान की परवाह किए बिना राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीतिअपनाएगी और सख्त कदम उठाएगी,जनता से यह अपील गई गई है कि अगर उन्हें किसी भी फर्जी बाबा या ढोंगी के बारे में जानकारी हो। तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें, ताकि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा सकें।**

भारी हड़कंप- सभी राज्यों ने इसका संज्ञान लेना समय की मांग है। साथियों बात अगर हम ढोंगी नकली पाखंडी बाबाओं को समझने की करें तो,ढोंगी पाखंडी बाबा वो होते हैं जिनके पास, न तो शिक्षा और ना ही किसी मंदिर या मठ का दस्तावेज है, ऐसे ही लोगों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं, इसी के चलते शुक्रवार को देहरादून पुलिस ने ऐसे 25 लोगों को गिरफ्तार किया है,जिनके पास ना तो कोई ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा है और ना ही उनके पास किसी मठिया मंदिर का कोई ऐसा दस्तावेज जिससे यह साबित कर पाए कि वह सही मायने में साधु या संत है,ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन पकड़े गए 25 ढोंगी बाबाओं में अनेकों राज्यों के लोग शामिल है, उत्तर प्रदेश,हरियाणा, राजस्थान, असम ,उत्तराखंड के लोग हैं। वहीं इन 25 लोगों में से एक व्यक्ति बांग्लादेश का मूल निवासी भी पाया गया है, पुलिस को अंदेशा है कि साधु संन्यासियों का वेश अपनाकर कई मुजरिम भी आम जनमानस के बीच मौजूद हो सकते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही गई है, इसमें सभी जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जिले में इस तरह के साधु-संतों का पेश धारण कर सड़क के किनारे या फिर गली मोहल्ले में घूमने वाले बाबों को भी चिन्हित कर पकड़े। साथियों बात अगर हम उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं को पकड़ने ऑपरेशन कालनेमि की करें तो, देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने वाले पाखंडी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है, इसी के तहत ऑपरेशन कालनेमि के नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है,इस अभियान के अंतर्गत जो भी लोग नकली साधु बन कर या साधुओं की वेशभूषा अपनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं।देवभूमि उत्तराखंड में पग-पग पर आध्यात्मिक स्थल है,

उसके बाहर साधु-संत और बाबा भी मौजूद रहते हैं, इनमें से कई तो सच्चे साधु-संत हैं लेकिन कई फर्जी भी, इन फर्जी बाबाओं के पास ज्ञान तो ना के बराबर होता है लेकिन आडंबर पूरा,अब उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे फर्जी बाबाओं को धर-पकड़ के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा है, ऑपरेशन कालनेमि इस ऑपरेशन के तहत देहरादून में 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है ये सभी नकली साधु या बाबा आम लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है,उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं,

कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमि की शुरुआत की,इसमें सभी जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने जिले में इस तरह के साधु-संतों का पेश धारण कर सड़क के किनारे या फिर गली मोहल्ले में घूमने वाले बाबो को भी चिन्हित कर पकड़े, इस अभियान पर कार्यवाही करते हुए दून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 25 ऐसे बाबाओं को हिरासत में लिया गया है, जो कि किसी प्रकार के संगठन से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सके,पुलिस को अंदेशा है कि साधु संन्यासियों का वेश अपनाकर कई मुजरिम भी आम जनमानस के बीच मौजूद हो सकते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इस अभियान को आगे भी जारी रखने की जरूरत है तथा इसे पूरे भारत में सभी राज्यों ने लागू करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की धार्मिक, जातीय या पंथीय पहचान की परवाह किए बिना राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और सख्त कदम उठाएगी, जनता से यह अपील गई गई है कि अगर उन्हें किसी भी फर्जी बाबा या ढोंगी के बारे में जानकारी हो, तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें, ताकि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा सकें,सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर जनता को गुमराह करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए,उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की धार्मिक, जातीय या पंथीय पहचान की परवाह किए बिना राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीतिअपनाएगी और सख्त कदम उठाएगी,जनता से यह अपील गई गई है कि अगर उन्हें किसी भी फर्जी बाबा या ढोंगी के बारे में जानकारी हो।

तो तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें, ताकि उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा सकें। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सरकार का ऑपरेशन कालनेमि- ढोंगी नकली पाखंडी साधु संतों में भारी हड़कंप- सभी राज्यों ने इसका संज्ञान लेना समय की मांग,आध्यात्मिक आस्था की प्रतीक भारतीय देवभूमि पर आस्था पूजा श्रद्धा के नाम पर ठगी करने वाले नकली बाबाओं पर शिकंजा कसना जरूरी, आध्यात्मिक आस्था व देवभूमि की छवि धूमिल करने वाले पाखंडी ढोंगी नकली बाबाओं की सफल धरपकड़-उत्तराखंड सरकार का कालनेमि ऑपरेशन सराहनीय है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

लोहगढ़ में बन रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए 26 लाख रुपये का दिया योगदान

चंडीगढ़ ।

सिख विरासत के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देते हुए तीन व्यक्तियों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल फाउंडेशन ट्रस्ट, लोहगढ़ को कुल 26 लाख रुपये का दान प्रदान किया। दान राशि के चेक यहां चंडीगढ़ में केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल को औपचारिक रूप से सौंपे गए। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के विशेष कार्याधिकारी डॉ. प्रभलीन सिंह भी उपस्थित थे, जो ट्रस्ट के कार्यों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए है। इस नेक कार्य में सहयोग देने के लिए आगे आए दानदाताओं में

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को सौंपे ट्रस्ट के नाम दान राशि के चेक

बाबा बंदा सिंह बहादुर के अद्वितीय साहस और बलिदान की स्मृति में किया जा रहा स्मारक का निर्माण

एनबीएस और स्पेस फाइव आर्किटेक्ट ग्रुप के निदेशक श्री हरकरण सिंह बोपाराय शामिल है, जिन्होंने 11 लाख रुपये का योगदान दिया; एके कंस्ट्रक्शन ग्रुप के अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा, जिन्होंने 10 लाख रुपये का दान दिया; और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्राधिकरण के सदस्य एवं वड़ैच होम्योपैथिक क्लिनिक, पेहेवा के संस्थापक डॉ. अवनीत सिंह वड़ैच ने 5 लाख रुपये का योगदान देकर सहयोग प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट के मार्गदर्शन में भारत के प्रथम संप्रभु सिख शासन स्थापित करने वाले पूजनीय सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर के अद्वितीय साहस और बलिदान की स्मृति में किया जा रहा है। इस स्मारक का उद्देश्य उनकी अदम्य वीरता का प्रतीक बनना और भारतीय इतिहास के इस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की विरासत को संरक्षित करके भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हरियाणा के करनाल को देश के टॉप 15 स्वच्छ शहरों में मिला स्थान

चंडीगढ़ ।

केंद्र सरकार द्वारा देश के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के आकलन के लिए किये गए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के घोषित परिणामों में हरियाणा के करनाल शहर को देश के टॉप 15 शहरों में स्थान मिला है। इसके लिए करनाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17 जुलाई को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करनाल नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाईस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्र ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह करनाल शहर के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि प्रदेश का एक शहर देश के 15 स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से सोनीपत नगर निगम को उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में

सोनीपत नगर निगम को भी मिलेगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड 17 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

करनाल व सोनीपत की रैंकिंग, शहरों के विकास और स्वच्छता के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें उम्मीद है कि यह उपलब्धि हमारे शहरों को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल का भी संकल्प है कि हरियाणा प्रदेश न केवल गंदगी से मुक्त प्रदेश बने, बल्कि स्वच्छ राज्य भी बने।

सदैव हमारी यादों में बने रहेंगे शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु सदैव हमारी यादों में रहेंगे। मुख्यमंत्री आज रोहतक, देव कॉलोनी स्थित स्क्वाड्रन लीडर शहीद लोकेंद्र सिंह सिंधु के घर पहुंचे, उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिवार जनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और उनका हौसला बंधाया। उन्होंने कहा कि लोकेंद्र सिंह सिंधु सेना के जांबाज अधिकारी थे। सेना में रहकर वे लगातार देश की सेवा के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत लोकेंद्र सिंह सिंधु की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता हरबंस लाल मलिक के घर भी गए। पिछले दिनों बीमारी के चलते हरबंस लाल मलिक का निधन हो गया था। उन्होंने हरबंस लाल मलिक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

पूर्व की सरकारों ने ओबीसी मेहनतकश वर्ग के साथ केवल धोखा किया: कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा

चंडीगढ़ ।भिवानी में सन्त महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अन्तर्गत मनाये गए महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के राज्यस्तरीय समारोह के संयोजक एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा आज का दिन प्रजापति समाज के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने अपने सम्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रजापति समाज से जुड़ी कई मांगे भी रखी। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रजापति समाज मेहनतकश समाज है, यह मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है। पूर्व की सरकारों के अंदर इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने ना सिर्फ इस समाज को सम्मान दिया, साथ ही हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। पूर्व की सरकारों ने ओबीसी मेहनतकश वर्ग के साथ केवल धोखा किया था, उस समय इस समाज के पास ना तो ज्यादा पॉलिटिकल पॉवर होती थी और ना ही उनके पास पैसा होता था, इसलिए हमारे बच्चे सरकारी नौकरी के योग्य होते हुए भी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने जहां बिना पर्ची, खर्ची इस समाज के युवाओं को सम्मान देने का काम किया, बल्कि बैकलॉग को भरने की दिशा में भी काम किया। कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती के राज्यस्तरीय समारोह के निमंत्रण के लिए उन्हें 22 जिलों में जाने का मौका मिला। लोगों ने इतनी भागीदारी दिखाई, इसके लिए वो आभारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बैकवर्ड समाज की क्रीमिलेयर बढ़ाने की मांग को पूरा किया है। मंच से कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने प्रजापति समाज को रोहतक के सेक्टर में हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार 1 हजार गज का प्लाट देने की मांग के अलावा, फतेहाबाद में दी गयी आधा एकड़ जमीन के कलेक्टर रेट से सम्बंधित मांग के अलावा अलग अलग एरिया से जुड़ी एक दर्जन के करीब मांगे रखी। उन्होंने क्लास वन और क्लास टू की नौकरियों में भी ओबीसी के लिये केंद्र सरकार की तर्ज पर कोटा बढ़ाने की मांग रखी। श्री गंगवा ने कहा प्रदेश के वैसे तो सरकार माटी कला बोर्ड के माध्यम से इस समाज के लिए कार्य कर रही है, लेकिन इसी ओर मदद करते हुए इसके लिए विशेष बजट रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं को बनाया जाये, जिससे इस समाज और युवाओं को रोजगार मिल सके तथा इनका उत्थान हो सके। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया कि महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती को राज्य स्तर पर मनाया गया।

भाजपा राज में अपराध का अमृत काल, हरियाणा में गैंगस्टर्स का आतंक, दो माह में 30 से ज्यादा वारदातें

कैथल । ढांड रोड स्थित किसान भवन में रविवार को राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला व विधायक आदित्य सुरजेवाला ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए। इस मौके पर सुरजेवाला ने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राज में अपराध का अमृत काल चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा सीएम के पास खुद गृह विभाग है और जिस तरह से अपराध का बेतहाशा विकास हो रहा है, इसमें नायब सैनी नाकाम साबित हो चुके है। पूर्व की भाजपा सरकारों में गुंडाराज और माफिया राज हमेशा से चेहरा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री के जिले में व्यापारियों को सरेआम धमकियां दी जा रही है, कारोबारी दहशत में है। हरियाणा में आए दिन जघन्य अपराध की वारदातें हो रही है जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल है। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में गैंगस्टर्स का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, संगठित अपराध की खुलेआम सक्रियता ने राज्य को जंगलराज की ओर धकेल दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, सिरसा जैसे शहरों में दिनदहाड़े फायरिंग और धमकियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शराब माफिया और विदेशी गैंगस्टरों के बीच सांठगांठ ने अपराध को और बढ़ावा दिया है, जिसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। अपराधियों की हिमाकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे सरकार की ओर से शराब के ठेकों तक की बोली नहीं होने दे रहे हैं। भाजपा की नाक तले अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि मई और जून महीने में हत्या, रंगदारी, फायरिंग की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई है और सैनी सरकार अपने सत्ता के सिंहासन पर आंख मूंदकर बैठी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 1996 से 1999 में जब हविपा और भाजपा की सरकार थी तब गुंडाराज कायम था व 2000 से लेकर 2005 तक जब इनेलो और बीजेपी की सरकार थी तब कस्बों, शहरों, जिलों और सड़कों पर गैंगस्टर, माफियाओं और गुंडों से हरियाणा को शर्मसार होना पड़ा था। आज फिर वही दहशत का दौर आ गया है।

यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, रेलवे पुल पर ट्रेन की टक्कर से नहर में गिरी दो सगी बहनें; एक की मौत

यमुनानगर। यमुनानगर जगाधरी स्टेशन के पास रेलवे पुल पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। शार्टकट के चक्कर में रेलवे पुल को पार करते समय दो सगी बहनें ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन की टक्कर से दोनों बहनें पुल से पश्चिमी यमुना नहर में जा गिरी। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक का पैर कट गया। जबकि बाकी हिस्सा नहर में जा गिरा। गोताखोर राजीव कुमार व उसकी टीम ने सर्चिंग करते हुए उस महिला का शव बरामद कर लिया लेकिन उसकी बहन का अभी तक पता नहीं लग सका है। मृतका की पहचान तीर्थनगर की टपरिया निवासी 26 वर्षीय कविता के रूप में हुई है। उसकी बहन गीता का अभी पता नहीं लगा है। तीर्थनगर की टपरिया निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव भायला कलां के रहने वाले है। यहां आरा मशीन पर कार्य करते हैं। उसकी पत्नी कविता व साली गीता रविवार को बाजार में गई हुई थी। दोपहर लगभग दो बजे वह बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान रेलवे पुल पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। उसकी पत्नी का शव मिल गया है लेकिन गीता का अभी पता नहीं लगा है। गीता की लगभग चार माह पहले ही शादी हुई है। गोताखोर राजीव कुमार ने बताया कि उनकी टीम ने जब शव को निकाला तो उसके पैर का हिस्सा नहीं था। इस महिला का पैर कटकर ट्रेन की पटरियों के बीच फंस गया था। वह हिस्सा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मृतका के छह वर्ष का बेटा व एक वर्ष की बेटी है। हमीदा पुलिस चौकी प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि दो महिलाओं के नहर में डूबने की जानकारी मिली। ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। जीआरपी को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर सख्ती बरतेगी पुलिस, चलेगा सर्च अभियान; भेजे जाएंगे बॉर्डर पार

फतेहाबाद।

जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी मूल के लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के जिले में रह रहा पाया जाता है, तो उसे तत्काल हिरासत में लिया जाए और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद बॉर्डर पार भेजा जाए। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और आंतरिक कानून-व्यवस्था की दृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है। हाल के समय में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की सूचनाएं भी प्राप्त हुई है, जिसके चलते ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई है।

ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों पर विशेष अभियान

जिलेभर के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, गोदामों, अस्थायी मजदूर बस्तियों तथा अन्य श्रमिक स्थलों पर विशेष अभियान चलाएं। इन जगहों पर कार्यरत मजदूरों की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके पास भारत में रहने के वैध दस्तावेज हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है, या उसके पास वैध कागजात नहीं होते, तो उसे तुरंत डिटेन किया जाए और आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाए।

चौकी प्रभारी करेंगे निरीक्षण

एसपी ने आदेश दिया है कि इस अभियान को गंभीरता से लिया जाए और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अधिकारी इस कार्य में कोताही बरतता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय एसडीएम की मदद से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए और डिटेन किए गए लोगों को बॉर्डर पार भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

अन्य विभागों के साथ समन्वय से चलेगा अभियान

इस पूरे अभियान को प्रभावी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्व विभाग, खुफिया इकाइयों, नगर परिषद, श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ईंट भट्ठा मालिकों, ठेकेदारों, फैक्ट्री संचालकों और अन्य रोजगार प्रदाताओं को भी चेतावनी दी गई है कि वे बिना दस्तावेज वाले किसी भी श्रमिक को काम पर न रखें। यदि कोई मालिक जानबूझकर ऐसे लोगों को शरण या रोजगार देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एक गंभीर प्रयास है। अवैध नागरिकों की मौजूदगी से न सिर्फ सुरक्षा जोखिम बढ़ते है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के रोजगार, संसाधनों और सामाजिक ढांचे पर भी दबाव बनता है। पुलिस का यह अभियान आने वाले दिनों में और भी व्यापक रूप से लागू किया जाएगा-सिद्धांत जैन, एसपी फतेहाबाद।

मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन में दौड़ लगाकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया प्रेरित

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कैथल में आयोजित हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी कैथल में आयोजित हाफ मैराथन के विजेताओं को सम्मानित करते हुए।

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करीब साढ़े 10 वर्षों से नशे की समस्या के खिलाफ हमारे युवा पूरे हरियाणा प्रदेश में एकजुट होकर कार्य कर रहे है। पिछले दिनों पूरे हरियाणा में नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब साढ़े 7 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी रविवार सुबह कैथल में अंबाला रोड पर आयोजित हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाने से पूर्व हजारों की संख्या में इस आयोजन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। हाफ मैराथन के ब्रांड एंबेसडर पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह व पर्वतारोही रीना भट्टी ने भी हाफ मैराथन में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी दौड़ लगाकर युवाओं को स्वस्थ रहने व नशे के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, ताकि प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है, जो व्यक्ति को ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देती है। यह

युवा हैं देश का भविष्य, युवा स्वस्थ होगा तो समाज, प्रदेश और देश करेगा तरक्की-मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं का होगा अहम योगदान

प्रदेश सरकार हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजनों के माध्यम से नशे के खिलाफ कर रही है प्रदेशवासियों को जागरूक

न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि आज वे संकल्प लें कि वे न तो स्वयं नशा करेंगे और दूसरों को भी नशा न करने के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि नशा समाप्त होगा तो हमारा युवा स्वस्थ होगा और समाज, प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन है, जिसे पूरा करने में युवाओं का अहम योगदान रहेगा।

उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह हम सबका संकल्प है। इसको पूरा करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में भाग ले रहे हजारों की संख्या में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, खिलाड़ी, पुलिस के जवान, स्वयंसेवकों को देखकर उन्हें विश्वास है कि हरियाणा को नशा मुक्त करने का हमारा सपना अवश्य साकार होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ रखने व उन्हें नशे की लत से दूर रखने के लिए प्रदेश में खेल सुविधाओं का विस्तार किया है। इसके साथ-साथ हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत मैराथन जैसे आयोजन करके युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम धाकड़ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आउटरीच कार्यक्रम के तहत पुलिस व जनता के बीच सहयोग व सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के साथ-साथ नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को समय दें। अगर कोई युवा गलत संगत में पड़ जाए तो उसे उस गर्त से निकालने का प्रयास करें।

युवाओं संग दौड़े मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने रास्ते में लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने आयोजन स्थल पर पहुंच कर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर विधायक श्री सतपाल जाम्बा, पूर्व राज्यमंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, पूर्व विधायक श्री लीला राम, कुलवंत बाजीगर, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी (कम्युनिटी, पुलिसिंग एवं आउटरीच) श्री पंकज नैन, जिला प्रशासन से डीसी प्रीति, एसपी श्रीमती आस्था मोदी मौजूद रहे।

मुशायरा ज़ौक़ ए सुख़न
दरिया ए सुख़न फाउंडेशन और आख़िरी सफ़ा की जानिब से

नई दिल्ली स (आकाश शर्मा) मंडावली वेस्ट विनोद नगर के मशहूर शायर असलम बेताब की रहनुमाई में हिंदुस्तान के मशहूर शायर वसीम नादिर के जन्मदिवस के उपलक्ष में एक खूबसूरत मुशायरा का आयोजन किया गया जिसमें हिन्दुस्तान के मशहूर शायर सलमान सईद, यासिर ईनाम आक़िब जावेद, तस्लीम आरफी, कुणाल वर्मा, आक़िब शाद, खालिद अख़लाक़, फरहतुल्लाह खान, शिराज़ खान, सृष्टि सिंह, मुस्कान मनोद, सरमद खान, शफ़ीक़ सैफी, रिज़वान अंसारी, आरिश हाफी, फुरक़ान अंसारी के साथ साथ खुद वसीम नादिर ने भाग लिया ... इस मुशायरे की सदारत वसीम नादिर ने की और निज़ामत आक़िब जावेद ने की .. प्रोग्राम के अंत में दरिया ए सुख़न फाउंडेशन के प्रधान जुबैर अहमद और आख़िरी सफ़ा के प्रधान फुरक़ान अंसारी ने सभी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया

.किराएदार की आँखों में आ गए

आँसू

बनाए बैठे थे बच्चे मकान कागज पर

9यासिर खान इनाम

हम है ज़ंजीरों की खन खन के बिगाड़े हुए लोग

तेरी पाजेब की छन-छन में नहीं आ सकते

9सलमान सईद

तुम्हारे बा९द अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले

जनाज़ा अपनी मर्ज़ी से कहाँ कांधा बदलता है

9वसीम नादिर

सैल-ए-रवाँ ने ऐसे सितम ढाए है कि अब

छूटी हुई ज़मीन का रक़बा उदास है

9आक़िब जावेद

मैंने लफ्ज़ों में जो नमी की है

रो न पाया तो शायरी की है

शफ़ीक़ सैफी

ये जानकारी दरिया ए सुख़न फाउंडेशन की महा सचिव लक्ष्मी और सचिव तस्लीम आरफी ने दी

दिल्ली के नालों में गिरकर कैसे मर रहे बच्चे, जिम्मेदार कौन? प्रशासन, सरकार या कोई और...

बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी जिले के समयपुर गांव में गत रविवार को खुले नाले में गिरने से चार साल के बच्चे की मौत पर पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज किया है। लेकिन किसके विरुद्ध, यह एफआईआर में नहीं है। यही अक्सर होता है। इस तरह के मामलों में इसी वजह से जांच भी नाले में गाद की तरह जम जाती है। पुलिस कहती है कि जांच के बाद हम संबंधित विभाग या अधिकारी के खिलाफ नामजद एफआईआर करेंगे, लेकिन ऐसा कम ही मामलों में देखा जाता है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि नामजद एफआईआर नहीं होने के कारण जांच भी शिथिल पड़ जाती है। पुलिस आखिर तक यह पता नहीं लगा पाती है कि लापरवाही का जिम्मेदार अधिकारी कौन है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में सजा सुनने को कम ही मिलते हैं। 9 सितंबर 2021 किराड़ी के रोशन एन्क्लेव में गुजर रहे सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के नाले में डूबकर सात वर्षीय नमन की मौत हो गई थी। नाले की दीवार छोटी होने के कारण बच्चे खेलते हुआ गिर थे। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। करीब चार वर्ष बीत जाने के बाद भी दीवार की ऊंचाई नहीं बढ़ाई। पिता निजाम ने बताया कि आज तक उन्हें एफआईआर की कापी नहीं मिली। एसडीएम रोहिणी की ओर से मुआवजे की रकम के लिए वर्ष 2023 में कागजात जमा कराने के लिए कहा गया था। उन्होंने कागजात भी जमा कराए। अब अमन विहार थाने से इसपर रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक उन्हें इस मामले में नहीं प्रशासन और नहीं विभाग की ओर से कोई मदद मिली। 10 अगस्त 2024 रोहिणी सेक्टर-20 स्थित डीडीए के पार्क में बने छठ घाट में वर्षा का पानी भरा हुआ था। आठ वर्षीय तरुण खेलते हुए छठ घाट के अंदर गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई थी। मृतक अरुण के मामा ने बताया कि पुलिस के असंवेदनशील के कारण मामला दब गया। पुलिस ने उस समय लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया। जांच के बाद भी संबंधित विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार वे थाने का चक्कर लगाए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार से न तो किसी विभाग से कोई आया और नहीं प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई मदद मिली। 03 मार्च 2024 अलीपुर स्थित मोहम्मद पुर गांव में दिल्ली जलबोर्ड की सीवर लाइन डालने के लिए खोदाई चल रही थी। साइट पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। यहां से पैदल निकलते समय करीब 10 फुट गहरे गड्ढे में रमेश चंद गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार के काफी जद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जलबोर्ड के संबंधित ठेकेदार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। रमेश के भाई ने बताया कि मामला रोहिणी कोर्ट में अभी लंबित है। अभी तक तीन बार ये तारीख पर जा चुके हैं। इसमें से एक ही तारीख पर ठेकेदार आया था। जिसके बाद वह नहीं आया। अभी तक इस मामले में न तो मुआवजा ही मिला और नहीं अभी किसी को सजा हुई है। 21 मार्च 2025 को तीन साल का बच्चा अपनी बड़ी बहन के साथ खजूरी में ब्लाक में गली में खेल रहा था। बच्चा चक्कर चला रहा था।

राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को किया नॉमिनेट

मशहूर वकील निकम, इतिहासकार मीनाक्षी जैन, पूर्व डिप्लोमैट हर्षवर्धन श्रृंगला और समाजसेवी सदानंदन शामिल

नई दिल्ली।

राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इनमें पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार रहे उज्ज्वल निकम शामिल हैं। निकम, 26/11 के मुंबई हमला समेत कई हाई-प्रोफाइल मामलों में पब्लिक प्रासिक्यूटर रहे हैं। इसके अलावा, केरल के वरिष्ठ समाजसेवी और शिक्षाविद सी. सदानंदन मास्टर, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन भी राज्यसभा जाएंगी। ये नियुक्तियां उन सीटों के लिए की गई हैं, जो पहले के नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से खाली हुई थीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 नामांकित सदस्य शामिल हैं। भारत की संसद में दो सदन होते हैं- लोकसभा और राज्यसभा। रायसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। संसद को दोनों सदनों का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है। इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है। फिर इस पर चर्चा होती है, उसके बाद सभी की सहमति या वोटिंग कराकर इसे पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाता है।

बिहार के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश-म्यांमार -नेपाल के लोगों की भी बड़ी संख्या- ईसी

पटना। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य जारी है। पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे थे कि बिहार में अवैध अप्रवासी भी यहां के मतदाता बन गए हैं।

अब इसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की गहन समीक्षा के दौरान पाया कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों बड़ी संख्या में शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर इसकी जांच की तो पता चला।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि अवैध प्रवासियों के नाम अंतिम निर्वाचन सूची में नहीं शामिल किए जाएंगे। यह 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी, इसके लिए ऐसे लोगों की उचित जांच एक अगस्त के बाद की जाएगी। चुनाव आयोग अंततः भारत भर में विदेशी अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा करेगा, जिसमें उनके जन्म स्थान की जांच की जाएगी। बिहार इस वर्ष चुनावों में जाएगा, जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे पांच अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव 2026 में निर्धारित हैं।

243 विधानसभा क्षेत्रों में बारीकी से निगरानी की जा रही है

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और 963 सहायक ईआरओ (एईआरओ) सहित क्षेत्र स्तरीय टीमों की निर्वाचन अधिकारी की ओर से बारीकी से निगरानी की जा रही है। चुनाव आयोग के इन प्रयासों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 1.5 लाख बीएलए भी घर-घर जाकर हर मौजूदा मतदाता को शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अब तक 80.11फीसदी मतदाता जमा कर चुके हैं गणना प्रपत्र पाया गया है।

मतदाता सूची वितरण का काम पूरा

100 फीसदी मुद्रण पूरा होने और अपने पते पर पाए गए सभी मतदाताओं को मतदाता सूची वितरण का काम लगभग पूरा होने के बाद, आज शाम 6 बजे तक संग्रह 6,32,59,497 या 80.11 फीसदी पार कर गया। इसका मतलब है कि बिहार में हर 5 में से 4 मतदाताओं ने मतदाता सूची जमा कर दी है। इस गति से, अधिकांश ईएफ 25 जुलाई 2025 से काफी पहले एकत्र किए जाने की संभावना है।

बीजेपी ने विपक्ष को घेरा

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद, कांग्रेस, वामपंथी और उनके समर्थक चुनाव आयोग पर लगातार ऐसे विदेशी नामों को सूची में शामिल करने का दबाव बना रहे हैं, ताकि वे अपना वोट बैंक बना सकें। मालवीय ने कहा, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के विदेशी नागरिकों के नाम शामिल पाए गए हैं। यह खुलासा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान हुआ।

मणिपुर में पांच उग्रवादी गिरफ्तार

मणिपुर। मणिपुर के तीन जिलों से सुरक्षाबलों ने विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलेई यावोल कन्ना लूप (केवाईकेएल) के दो सक्रिय कैडरों को शनिवार को इंफाल पूर्वी जिले के लाइकलीग से पकड़ा गया, जबकि कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी(ताइबांगनबा) के एक सदस्य को शुक्रवार को बिष्णुपुर के टोंग्लाओबी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों ने शनिवार को इंफाल पूर्वी के कोंगपाल से प्रतिबंधित कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एपीयूएनबीए) के एक सक्रिय कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया तथा थौबल जिले के वांगजिंग बाजार से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, पांच घायल

राजगढ़। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर पचोर के देहरी जोड़ के पास ओवरब्रिज पर एक कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाने से यह हादसा हुआ। पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया कि कार देहरी जोड़ ओवरब्रिज पर पहुंची ही थी कि चालक को झपकी आ गई और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मुकेश बारेला (28) और देवेंद्र बारेला (40) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का पचोर अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया और फिर उन्हें राजगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बामनिया ने बताया कि कार में सवार सभी लोग गुना जिले के बमोरी के मैदा और माना गांव के निवासी थे।

बिहार चुनाव/ 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का किया ऐलान

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि बिहार सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले पांच वर्षों (2025-2030) में युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के वास्ते कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राय सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुमार की यह घोषणा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार सुबह सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''अगले पांच साल में (2025 से 2030) वर्ष 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राय के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा, ''अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 'सात निश्चय के तहत जारी कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास के लिए एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि राय के युवाओं को कौशल विकास की नयी दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि 2005 से 2020 के बीच बिहार के आठ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, ''युवाओं को सरकारी नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराने की गति को और तेज करने के लिए, 2020 में सुशासन के कार्यक्रम 'सात निश्चय-2 के तहत हमने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में, इस लक्ष्य को बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य कर दिया गया।

सीएम नीतीश का बड़ा दांव

उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन जरूरी, तभी बचेगा महाराष्ट्र : राउत

मुंबई।

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राऊत ने रविवार को कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों ठाकरे भाई एक हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र को नई दिशा मिलेगी। साथ ही राऊत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा की नीति है पहले मुंबई को लूटो, फिर उसे केंद्रशासित प्रदेश बनाओ, फिर विदर्भ को अलग राज्य बनाकर महाराष्ट्र की एकता को खत्म कर दो। बता दें कि संजय राऊत ने यह बात शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक-ठोक में लिखी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को महाराष्ट्र की एकता या मराठी अस्मिता से कोई मतलब नहीं है।

देवेंद्र फडणवीस पर भी साधा निशाना

राऊत ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक समय नागपुर में विदर्भ मेरा अपना राय है, जैसे बैनर लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। राऊत ने कहा कि अगर उद्धव और राज ठाकरे की एकता बनी नहीं रही, तो मुंबई अदाणी-लोढ़ा के हाथों चली जाएगी, और एक दिन यह महाराष्ट्र का हिस्सा भी नहीं रह जाएगी। राऊत ने लिखा कि ठाकरे भाइयों का साथ आना मराठी जनता के लिए आशा की किरण है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, अब तक दोनों दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह जरूरी है कि गठबंधन हो। तभी महाराष्ट्र को सही दिशा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ठाकरे दबाव में आ जाएंगे, वे मुगालते में हैं। राऊत ने यह भी कहा कि मराठी जनता को सबसे पहले मुंबई और ठाणे को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आने वाले समय में यहां नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं।

मानसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सोनिया गांधी ने बुलाई 15 जुलाई को बैठक

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की योजना बना रही है। विपक्षी दल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी निर्वाचन आयोग के कदम पर कड़ी आपत्ति जता सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की मांग भी करती रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी अपने 10 जनपथ स्थित आवास पर करेंगी। सरकार ने घोषणा की है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा, जो पहले से तय समय से एक सप्ताह ज्यादा है। इससे बड़ी विधायी कार्यसूची का संकेत मिलता है। पहले यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लंबी अवधि वाला सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को सुगम बनाने सहित कई प्रमुख विधेयक लाने की योजना बना रही है। सरकार, 'परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम' और 'परमाणु ऊर्जा अधिनियम' में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने संबंधी केंद्रीय बजट की घोषणा पर अमल किया जा सके। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग कर रहा है। विपक्षी दल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त कराने में मध्यस्थता का दावा किया है। हालांकि सरकार ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है।

नजरबंदी और प्रतिबंध पर राजनीतिक दलों में उबाल, नेताओं का केंद्र सरकार पर तीखा वार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आज मनाए जाने वाले कश्मीर शहीद दिवस पर इस साल भी विवाद गहरा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन ने इस दिन किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को या तो नजरबंद कर दिया गया या हिरासत में ले लिया गया। यह दिन 1931 में हुए नरसंहार की बरसी के तौर पर मनाया जाता है, जब ब्रिटिश शासन के अधीन तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोग मारे गए थे। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने श्रीनगर के कई इलाकों में कड़े प्रतिबंध लगाए और शहीदों के कब्रिस्तान की ओर जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उमर अब्दुल्ला ने इन प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 13 जुलाई का नरसंहार हमारा जलियांवाला बाग है। जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा किया। कश्मीर पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। यह कितनी शर्म की बात है कि ब्रिटिश शासन के हर रूप के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को आज सिर्फ इसलिए खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान थे। आज हमें उनकी कब्रों पर जाने का मौका भले ही न मिले, लेकिन हम उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे।

पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल की दूरी वाले बयान से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब आप शहीदों के कब्रिस्तान की घेराबंदी करते हैं, लोगों को मजार-ए-शुहदा जाने से रोकने के लिए उनके घरों में बंद कर देते हैं, तो यह बहुत कुछ कहता है। 13 जुलाई हमारे उन शहीदों को याद करता है जो देश भर के अनगिनत अन्य लोगों की तरह, अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए। वे हमेशा हमारे नायक रहेंगे। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी अपनी नजरबंदी की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार कश्मीर के लोगों के लिए पवित्र चीजों को फिर से परिभाषित करने पर इतनी उत्सुक क्यों है। 13 जुलाई को दिए गए बलिदान हम सभी के लिए पवित्र है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि खून से सने इतिहास कभी मिटते नहीं। इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 1931 के विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों की याद में 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश बहाल करने का आग्रह किया था। हालांकि, इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे इस ऐतिहासिक दिन पर फिर से तनाव बढ़ गया है।

महाराष्ट्र में भाषा को लेकर फिर बवाल, ऑटो ड्राइवर के साथ एमएनएस-शिवसेना कार्यकर्ताओं ने की मारपीट

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार इलाके में हिन्दी बोलने वाले एक ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इस घटना के पीछे की वजह सिर्फ यह थी कि ऑटो चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा था- मैं हिन्दी बोलूंगा। शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना (उद्धव गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति भावेश पडोलिया और एक ऑटो रिक्शा चालक के बीच बहस हो गई थी। जब भावेश ने ऑटो चालक से पूछा कि वह मराठी में बात क्यों नहीं कर रहा है, तो चालक ने कहा, मैं हिन्दी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, मराठी नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शनिवार को शिवसेना और मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरार स्टेशन पर उस ड्राइवर को पहचानकर घेर लिया और सबके सामने उस पर थप्पड़ बरसाए। इस घटना में महिलाएं भी शामिल थीं। घटना के वक्त शिवसेना के विरार शहर प्रमुख उदय जाधव भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से कहा, अगर कोई महाराष्ट्र, मराठी भाषा या मराठी मानुष का अपमान करेगा तो उसे शिवसेना वाले जवाब देना जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्राइवर ने मराठी अस्मिता का अपमान किया है इसलिए हमने उसे सिखाया कि महाराष्ट्र में रहकर ऐसी बातें नहीं चलेंगी। उसे माफी मांगनी ही पड़ी। इस मामले को लेकर पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

'अखिलेश का पूरा कार्यकाल हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टिकरण का रहा', शिव भक्तों पर लाठी और राम भक्तों पर गोली चलवाई : केशव मौर्य

लखनऊ। (वेबवार्ता) कावड़ यात्रा पर सपा द्वारा दिए जा रहे बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने रामभक्तों पर गोली चलवाई है और शिव भक्तों पर लाठी चलवाई है। अखिलेश का पूरा कार्यकाल हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टिकरण का रहा है। सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली न करें। सपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। विपक्ष को केवल राजनीति करनी है और जनहित के मुद्दों से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। केशव मौर्य ने कहा कि सरकार में रहते हुए केवल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहे। सरकार केवल जहां बच्चे नहीं है उन विद्यालयों को मर्ज किए है। हाईकोर्ट ने भी इसपर मुहर लगाते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया है। शिक्षा को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। केशव प्रसाद मौर्य ने महाराष्ट्र में इनदिनों भाषा विवाद पर कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जनाधारहीन हो गए है। देश की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। दुर्व्यवहार करना गलत है। केशव ने प्रदेश अध्यक्ष के चयन के मुद्दे पर कहा कि जो पार्टी का काम है वो पार्टी को करने दीजिए। 2027 के चुनाव में वो खाली हाथ रहेंगे। विपक्ष के किसी भी बयान का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी सरकार सभी पर फूल बरसा रही है।

अमरनाथ यात्रा के दौरान 3 बसें आपस में टकराई, 10 यात्री घायल; सभी अस्पताल में भर्ती

श्रीनगर। (वेबवार्ता) जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को अमरनाथ यात्रा के काफिले की तीन बसें आपस में टकरा गई, जिससे कम से कम 10 तीर्थयात्री घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे में तीनों बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रभावित बसों में सवार अन्य तीर्थयात्रियों को अतिरिक्त बसों में स्थानांतरित किया गया, और काफिला अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो गया। वहीं बुधवार सुबह भी नरसू इलाके में डिवाइडर से टकरा गया था। इस हादसे में कार में सवार पांच श्रद्धालुओं घायल हो गए। एक श्रद्धालु को सिर में अधिक चोट आई, जबकि चार मामूली रूप से घायल हुए थे। यह हादसा सुबह करीब 6:17 बजे उस समय हुआ, जब जत्थे में शामिल तेज रफ्तार कार नंबर एचआर40एच6485 पहलगाम की ओर जाते समय नरसू इलाके में नियंत्रण खो कर डिवाइडर से टकरा गई। कार के टकराने से हुई जोरदार आवाज सुन कर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान व राहत व बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे।